आम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें रहती हैं। इस बार वित्तमंत्री के पिटारे में उनके लिए कुछ न कुछ खास होगा। रियल एस्टेट क्षेत्र के लोगों को भी इस बार वित्तमंत्री जी से काफी उम्मीदें हैं।

## रियल एस्टेट

प्रदीप मिश्रा, रिसर्च हेड, इंडिया हाउसिंग

- एनआइजी व अफॉर्डेबल हाउसिंग के लिए विशेष बजट दिया जाए। ब्याज दरों में भी कमी की जाए।
- रेजीडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर से 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स हटाया जाए।
- इसीबी (एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग) पर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए।
- एक्सपोर्ट ड्यूटी इस क्षेत्र में बहुत अधिक है, इसे दो से तीन प्रतिशत तक घटा देना चाहिए।

यशेष यादव, मुख्य आर्किटेक्ट, दक्ष क्रिएशंस

- सभी रेजीडेंशियल व कमर्शियल बिल्डिंग्स पर ग्रीन बिल्डिंग का नियम लागू होना चाहिए।
- सभी निर्माण में ग्रीन एरिया व प्ले ग्राउंड का एरिया बढ़ाया जाना चाहिए।
- बिना पूरी कंस्ट्रक्शन व फिटिंग आदि हुए पजेशन नहीं देना चाहिए।
- विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त टैक्स का बोझ हटाया जाना चाहिए।

दीपक वढेरा, क्लाजिना कंसल्टेंट्स

- सरियल एस्टेट के लिए इंडस्ट्री स्टेट्स दिया जाए।
- हर समस्या के समाधान के लिए एक सिंगल विंडो बनाई जाए।
- हाउसिंग लोन व टैक्स छूट को बढ़ाया जाए।
- जीएसटी को लागू किया जाना चाहिए।

हसन मोहम्मद, निदेशक, प्रेक्सिस ग्रुप

- आवासीय लोग लेने में ब्याज दरों में कटौती
- भूमि संपरिवर्तन प्रक्रिया आसान होनी चाहिए
- ग्राहक व बिल्डरों के बीच पारदर्शिता बनाए रखने को नए कानून बनाने चाहिए
- इनकम टैक्स की छूट सीमा में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

प्रवीण अग्रवाल, चेयरमैन, नॉवेल ग्रुप

- रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए।
- सिंगल विंडों क्लियरेंस होनी चाहिए ताकि बिल्डरों को पजेशन देने में देरी न हो
- जीएसटी बिल लागू होना चाहिए।
- इस क्षेत्र में लगने वाले विभिन्न करों पर सरकार को फिर से सोचना चाहिए।

मुकेश मित्तल, निदेशक, केएनडी इंफ्रास्ट्रक्चर

- आम आदमी के लिए सस्ते फ्लैट व प्लॉट मुहैया करवाए जाने चाहिए।
- बिल्डर्स के लिए एक ही पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सभी लाइसेंस एक ही विंडो पर उपलब्ध हों।
- बैंक होम लोन कम दरों पर उपलब्ध करवाए जाएं
- बिल्डर्स को बिजली पानी कम दामों पर उपलब्ध करवाए जाएं।

यदि आपको भी कुछ कहना है तो हमें मेल कर सकते हैं... satyendra@nda.jagran.com